



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—संख्या 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

मई विल्ली, सोमवार, मार्च 29, 1982/चैत्र 8, 1904

No. 95] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 1982/CHAITRA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विधियां)

अधिकारी

मई विल्ली, 29 मार्च, 1982

सांख्यिकी 271 (अ).—गण्डपति द्वारा न्याय विधि विधियां
आवेदन संविधान की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संख्या 116

संविधान (राजस्व-वितरण) आदेश, 1982

राज्यपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त विधियों का प्रयोग
करते हुए यित्र आयोग की विकारियों पर विभार करने के पश्चात्
निम्नलिखित आवेदन करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आवेदन का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व-वितरण) आदेश,
1982 है।

2. साधारण बोह्य अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आवेदन
के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी
केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के बांद (1) के उपबंधों के प्रनुसार,
1 अप्रैल, 1981 से ग्राम्य होने वाले विधीय वर्ष में, निम्नलिखित
राशि को भारत की राजित निधि पर प्रभारित किया जाएगा:—

(क) नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिविष्ट प्रत्येक राज्य के
राजस्व के सहायता-भनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तम्भ
(2) से (6) में प्रत्येक के सामने विनिविष्ट राशि को उन
स्तम्भों में उल्लिखित सेवकरों के प्रशासन और सेवाओं से
संबंधित मात्रों के उन्नयन के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व
और पूर्जीगत प्रकृति के व्यय महे:

राज्य	निम्नलिखित से संबंधित मात्रों के उन्नयन के लिए					
	न्यायिक प्रशासन	पुलिस प्रशासन	जेल प्रशासन	राजस्व जिला और राजस्ट्री- जनजाति करण प्रशासन	स्टाम्प प्रशासन	सारणी (लाख रुपयोंमें)
1	2	3	4	5	6	
आन्ध्र प्रदेश	20.12	431.25	—	57.00	—	
आसम	18.31	261.62	—	51.05	—	
बिहार	24.00	602.74	127.08	484.00	19.58	
दिल्ली प्रदेश	0.82	112.67	—	17.54	8.00	
जम्मू-कश्मीर	1.00	—	11.50	58.94	—	
केरल	—	60.00	—	13.00	—	
मध्य प्रदेश	4.01	743.40	112.63	428.00	—	
मणिपुर	0.80	—	7.80	147.00	—	
मेघालय	—	92.88	16.66	50.50	—	
नागालैण्ड	28.00	100.00	—	—	—	
उड़ीसा	15.16	261.54	89.45	355.47	—	
राजस्वान	16.60	427.49	5.00	49.50	34.00	
तिकिटम	—	—	—	—	—	
तमिलनाडु	—	173.57	210.82	17.03	—	
पिंडिया	—	—	—	—	—	
उत्तर प्रदेश	73.30	2028.93	283.55	7.40	18.78	
पश्चिमी बंगाल	3.70	79.78	—	52.50	—	

परन्तु ऊपर विनिविष्ट राशि, सेक्टरों के प्रशासन और सेवाओं के संबंध में सामनों के उपर्युक्त के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी:

परन्तु यह भी कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर किया गया वास्तविक व्यय, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं से प्रकट होता है, उस प्रशासन के सामने ऊपर विनिविष्ट अनुदान की रकम से कम है तो इस प्रकार प्रधिक संदर्भ रकम किसी अन्य राशि या राशियों के बिन्दु, जो उसी प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेश हो जाए, समायोजित की जाएगी;

(ब) नीचे सारणी के स्तरम् (1) में विनिविष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तरम् (2) में उसके सामने विनिविष्ट राशि को, संविधान (राजस्व संवितरण) आवेदन, 1981 के प्रवीन शुद्ध व्याज वायित्व मटे संदर्भ अनुदान की हिताव में लेने के पश्चात इस निमित वित्त भागीदारों के सिकारिशों के अनुसार शुद्ध व्याज वायित्व महे, 1 प्रवीन, 1980 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उत्तिविष्ट राज्यों में से प्रत्येक राज्य के नए उद्धारों और ऋणों महे:

सारणी

राज्य	लालू रूपये में
(1)	(2)
हिमाचल प्रदेश	39.15
जम्मू-कश्मीर	679.06
मणिपुर	36.68
मेघालय	22.45
नागालैण्ड	76.28
उडीसा	727.04
सिक्किम	54.25
लिपुरा	30.28

परन्तु यदि वास्तविक उधार और ऋण के ग्रांट्स जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं से प्रकट होता है, वा उधार पर व्याज की दरें, ऊपर विनिविष्ट अनुदान के अवधारण में हिस्सा में लिए गए मुसंग आकड़ों से भिन्न हों तो इस प्रकार संवत्सर अनुदान की रकम किसी ऐसी राशि या राशियों के प्रति, जो उसी प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेश हो जाए, समायोजित की जाएगी/जाएंगी।

(2). 1 प्रवीन, 1981 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उपर्या (1) के बांड (क) और बांड (ख) के प्रवीन किसी राज्य को संदेश कोई राशि या राशियों उस राज्य को संदेश उस राशि या उन राशियों के अतिरिक्त होगी/होंगी जो उस वित्तीय वर्ष में संविधान (राजस्व संवितरण) आवेदन, 1979 के पैरा 4 के उप पैरा (1) के अनुसरण में उस राज्य को संदेश होगा।

एन० संजीव रेहड़ी,
राष्ट्रपति।

[सं० एफ० 19(1)/82-एल० आई०]
ए० बैंकट शूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1982

G.S.R. 271(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O.116

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1982

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1982.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1981, as grants-in-aid of the revenues of—

(i) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (6) of the said Table, towards expenditure, of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns:—

TABLE

State	For upgradation of standards relating to				
	Judi- cial ad- minis- tration	Police ad- minis- tration	Jail ad- minis- tration	Re- venue, Dis- trict and Tribal ad- minis- tration	Sta- mps, Regis- stration and Treas- ury ad- minis- trations
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Andhra Pradesh	20.12	431.25	..	57.00	..
Assam	18.31	261.62	..	51.05	..
Bihar	24.00	602.74	127.08	484.00	19.58
Himachal Pradesh	0.82	112.67	..	17.54	8.00
Jammu and Kashmir	1.00	..	11.50	58.94	..
Kerala	..	60.00	..	13.00	..
Madhya Pradesh	4.01	743.40	112.63	428.00	..
Manipur	0.80	..	7.80	147.00	..
Meghalaya	..	92.88	16.66	50.50	..
Nagaland	28.00	100.00
Orissa	15.16	261.54	89.45	355.47	..
Rajasthan	16.60	427.49	5.00	49.50	34.00
Sikkim
Tamil Nadu	..	173.57	210.82	17.03	..
Tripura
Uttar Pradesh	73.30	2028.93	283.55	7.40	18.78
West Bengal	3.70	79.78	..	52.50	..

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government.

Provided further that if the actual expenditure on such approved programme or programmes relating to any administration,

as revealed in the accounts of that year, is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the Table towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1980, after taking into account the grants paid towards net interest liability under the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1981 as per the recommendations of the Finance Commission in this regard:—

TABLE

State (1)	(Rs. in lakhs) (2)
Himachal Pradesh	39.15
Jammu and Kashmir	679.06
Manipur	36.68
Meghalaya	22.45
Nagaland	76.28

(1)	(2)
Orissa	727.04
Sikkim	54.25
Tripura	30.28

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of that year, or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above, the amount of grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of subparagraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1981, shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1979.

N. SANJIVA REDDY,
President."

[No. F. 19(1)/82-L.L]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

